भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3215

जिसका उत्तर गुरुवार, दिनांक 29 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक कारें तथा दोपहिया वाहन

3215. श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2020 तक सड़कों पर बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक कारें और दोपहिया वाहन उतारने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने तथा इलेक्ट्रिक कारों के लिए और अधिक ग्राह्यता प्रदान करने हेतु क्या रणनीति बनाई गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने और देशभर में विशेषकर हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करके आवश्यक अवसंरचना भी उपलब्ध कराने के लिए एक स्पष्ट नीति प्रारंभ करते हुए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रफुल पटेल)

(क)से(ग): जी, हां। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड वाहनों सहित) राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एन ई एम एम पी - 2020) नामक एक मिशन प्लान तैयार किया है। एन ई एम एम पी - 2020 बैटरी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए ऐसे वाहनों की मांग सृजित करने और वर्ष 2020 तक ऐसे वाहनों के विनिर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि करने के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उपयोग को सुकर बनाने के लिए हस्तक्षेपों की कड़ी के माध्यम से रोडमैप उपलब्ध कराता है। ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने और इलेक्ट्रिक कारों के लिए और अधिक ग्राह्यता प्रदान करने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा रही है।

(घ): इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने और हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करके आवश्यक अवसंरचना भी उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****